उत्तर प्रदेश

ई संदेश

16 अप्रैल 2026| अंक 201

सात दिन-सात पृष्ठ

- स्मार्ट बिजली मीटर और ओवरबिलिंग की शिकायतों पर सीएम योगी सख्त, जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश
- बुनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार, आय और आजीविका की स्थिरता के लिए बनेगी क्लस्टर-आधारित नई कार्ययोजना: सीएम योगी
- डिफेंस कॉरिडोर, स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन में निवेश करेगा डेनमार्क, यूपी के विकास मॉडल से प्रभावित हुए डेनिश राजदूत
- 'इनोवेट इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड' के विजन से यूपी बनेगी देश की 'डीप-टेक कैपिटल' मुख्यमंत्री
- स्वस्थ नागरिक से ही सशक्त और विकसित भारत का निर्माण संभव, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता जरूरी: सीएम योगी
- सैनिकों के त्याग से ही सुरक्षित है राष्ट्र, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव: राजनाथ सिंह
- लखीमपुर खीरी में 817 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 6,706 परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक: सीएम योगी
- लखीमपुर खीरी में 331 विस्थापित बंगाली परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक, मियांपुर गांव अब कहलाएगा 'रविन्द्रनगर'- सीएम योगी
- मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात,मुख्यमंत्री ने कहा- अब उत्सव है हमारी पहचान
- बाबा साहब की 135वीं जयंती पर 75 जिलों में प्रतिमाओं के संरक्षण का शिलान्यास
- मुख्यमंत्री ने टाटा के 10 लाखवें वाहन का किया फ्लैग-ऑफ यूपी बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब
- एआई और आधुनिक तकनीक के दम पर उत्तर प्रदेश भर रहा विकास की नई उड़ान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में किया टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे एआई और उन्नत तकनीक के द्वार

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

स्मार्ट बिजली मीटर और ओवरबिलिंग की शिकायतों पर सीएम योगी सख्त, जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 अप्रैल 2026 को स्मार्ट बिजली मीटरों और ओवरबिलिंग को लेकर मिल रही उपभोक्ताओं की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए गहन जांच के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और सही बिल मिलने पर भुगतान में हिचक नहीं करता। मुख्यमंत्री ने ओवरबिलिंग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दी कि उपभोक्ता की गलती न होने पर किसी भी सूरत में उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करने तथा टोल फ्री नंबर '1912' व सिंगल विंडो मॉडल के जरिए शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2017 के 1.65 करोड़ से बढ़कर 2026 में 3.71 करोड़ से अधिक हो गई है, जो 126 प्रतिशत की वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने डिस्कॉम्स के सुधरते प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए राष्ट्रीय रेटिंग और वितरण ढांचे को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्होंने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को तेज करने, लाइनों को चरणबद्ध रूप से भूमिगत करने और फॉल्ट-फ्री सप्लाई के लिए प्रिवेंटिव मेंटीनेंस को अनिवार्य बताया। प्रदेश में अब तक 84 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ने न्यूनतम पांच आवास वाले मजरों में बिजली पहुंचाने और कृषि फीडर को अलग करने का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया, ताकि ओवरलोडिंग से निजात मिल सके।

आगामी ग्रीष्मकालीन मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी तापीय इकाइयों को पूर्ण क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि घाटमपुर की 660 मेगावाट इकाई इसी अप्रैल माह में शुरू हो जाएगी। भविष्य की जरूरतों के लिए 5,600 मेगावाट की नई परियोजनाओं (मेजा, ओबरा-डी और अनपरा-ई) को शीघ्र स्वीकृति देकर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत स्थापित 4.60 लाख से अधिक रूफटॉप की प्रगति की सराहना करते हुए इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को कहा गया। साथ ही 'पीएम कुसुम योजना' और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विकास में तेजी लाने पर बल दिया गया। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने विजिलेंस टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चेकिंग के दौरान पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और आम आदमी को अकारण परेशान करने वाली कोई भी दमनात्मक कार्रवाई न हो।

बुनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार, आय और आजीविका की स्थिरता के लिए बनेगी क्लस्टर-आधारित नई कार्ययोजना: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 अप्रैल 2026 को स्पष्ट किया कि बुनकर केवल परम्परा के संवाहक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार हैं, इसलिए उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लखनऊ में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में हथकरघा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बुनकरों के सामने कच्चे माल की बढ़ती लागत, डिजाइन और आधुनिक तकनीक का अभाव तथा सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान केवल योजनागत सहायता से नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ एवं समन्वित तंत्र विकसित कर ही सम्भव है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एक परिणामोन्मुख और क्लस्टर-आधारित नई कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में पूरे देश में छठवें स्थान पर मजबूती से खड़ा है। कालीन, दरी एवं मैट के उत्पादन में प्रदेश अग्रणी भूमिका में है, जबकि बेडशीट, फर्निशिंग और ब्लैंकेट जैसे उत्पादों में भी राज्य की शानदार उपस्थिति दर्ज है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, देश का कुल हथकरघा निर्यात 1178.93 करोड़ रुपये रहा, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान 109.40 करोड़ रुपये (लगभग 9.27 प्रतिशत) रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुनकर बहुल क्षेत्रों की सटीक पहचान कर वहां नए क्लस्टर विकसित किए जाएं, ताकि उत्पादन, गुणवत्ता और विपणन को एक मंच पर एकीकृत किया जा सके। उन्होंने बल देते हुए कहा कि ये क्लस्टर केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहें, बल्कि इन्हें पूर्ण वैल्यू चेन के रूप में विकसित किया जाए, जहां डिजाइन, ब्राण्डिंग, पैकेजिंग और बाजार तक आसान पहुंच एक ही सुदृढ़ ढांचे के अंतर्गत सुनिश्चित की जा सके।

समीक्षा बैठक में क्लस्टर चयन, बेसलाइन सर्वे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, इन गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत अनुश्रवण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक क्लस्टर में सीमित संख्या में बुनकरों को संगठित कर उन्हें पंजीकृत इकाइयों के रूप में विकसित किया जाए, जिससे सामूहिक उत्पादन और विपणन की भावना को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही, इन क्लस्टरों को आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरणों और उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, जिससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में निरंतर सुधार हो सके। उत्पाद की सफलता को बाजार की मांग के अनुरूप बताते हुए उन्होंने डिजाइन और विपणन को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।

बुनकरों की आय बढ़ाने और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 'डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव' तथा 'डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बाइंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस' जैसे संस्थागत तंत्रों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और ब्राण्डिंग के तेजी से विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि बुनकरों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, पावरलूम बुनकरों के भारी-भरकम विद्युत बिलों में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हथकरघा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन को मिलकर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे बुनकरों की विद्युत लागत में भारी कमी आएगी और उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक राहत मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश का बुनकर समुदाय राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, व्यापक रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए ऐसी संतुलित, पारदर्शी और व्यावहारिक नीति तैयार की जाए, जिससे बुनकरों को वास्तविक राहत मिले, इस पारम्परिक उद्योग को नई गति प्राप्त हो और प्रदेश की गौरवशाली बुनकरी को एक सशक्त आधार मिल सके।

डिफेंस कॉरिडोर, स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन में निवेश करेगा डेनमार्क, यूपी के विकास मॉडल से प्रभावित हुए डेनिश राजदूत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 10 अप्रैल, 2026, को लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर भारत में डेनमार्क के राजदूत श्री राससमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंशन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच उत्तर प्रदेश में निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में सम्भावित साझेदारी को लेकर व्यापक और सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ निवेशकों के लिए पारदर्शी नीतिगत वातावरण, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध है। उन्होंने डेनमार्क की कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निवेशक को आवश्यक सहयोग, सरल प्रक्रियाएँ और सुरक्षित निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, जल प्रबन्धन, स्किल डेवलपमेण्ट, अवस्थापना विकास एवं हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ साझेदारी को अत्यन्त उपयोगी बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की सहभागिता से उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तान्तरण और सतत् विकास को नई गति मिलेगी। भेंट के दौरान डेनमार्क के राजदूत ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले भारत में निवेश की चर्चाओं में उत्तर प्रदेश का उल्लेख बहुत सीमित रहता था, किन्तु वर्तमान में यह राज्य निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है। राजदूत ने प्रदेश की विशाल जनसंख्या, कुशल मानव संसाधन और सुदृढ़ होती आधारभूत संरचना को इसकी प्रमुख ताकत बताते हुए इन ऐतिहासिक उपलब्धियों का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया।

डेनमार्क के राजदूत ने उत्तर प्रदेश में निवेश की व्यापक सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से डिफेंस कॉरिडोर में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में डेनमार्क का समृद्ध अनुभव है और वहां की कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में निवेश एवं तकनीकी साझेदारी के लिए बेहद उत्सुक हैं। साथ ही, 'वेस्ट-टू-एनर्जी' सेक्टर, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज में डेनमार्क की विशेषज्ञता का उल्लेख करते हुए उन्होंने इन क्षेत्रों में भी सक्रिय सहयोग की इच्छा जताई। जल प्रबन्धन के क्षेत्र में राजदूत ने बताया कि आईआईटी (बीएचयू) के साथ नदी पुनरुद्धार एवं जल शोधन से सम्बन्धित एक परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसके लिए वे शीघ्र ही वाराणसी का दौरा करेंगे। इसके अलावा, कम्प्रेस्ड बायोगैस सहित नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भी डेनिश कम्पनियों की रुचि से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

राजदूत ने शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र को भी दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में डेनमार्क की भागीदारी से नॉलेज ट्रांसफर एवं स्किल डेवलपमेण्ट को काफी बढ़ावा मिलेगा। एल्डरली हेल्थ केयर (बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल) सेक्टर में बढ़ती वैश्विक माँग को देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को भाषा प्रशिक्षण एवं आवश्यक कौशल प्रदान कर उन्हें अन्तरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहयोग का प्रमुख आयाम बताते हुए राजदूत ने कहा कि कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से टिकाऊ कृषि एवं वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकता है।

‘इनोवेट इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड’ के विजन से यूपी बनेगी देश की ‘डीप-टेक कैपिटल’ मुख्यमंत्री

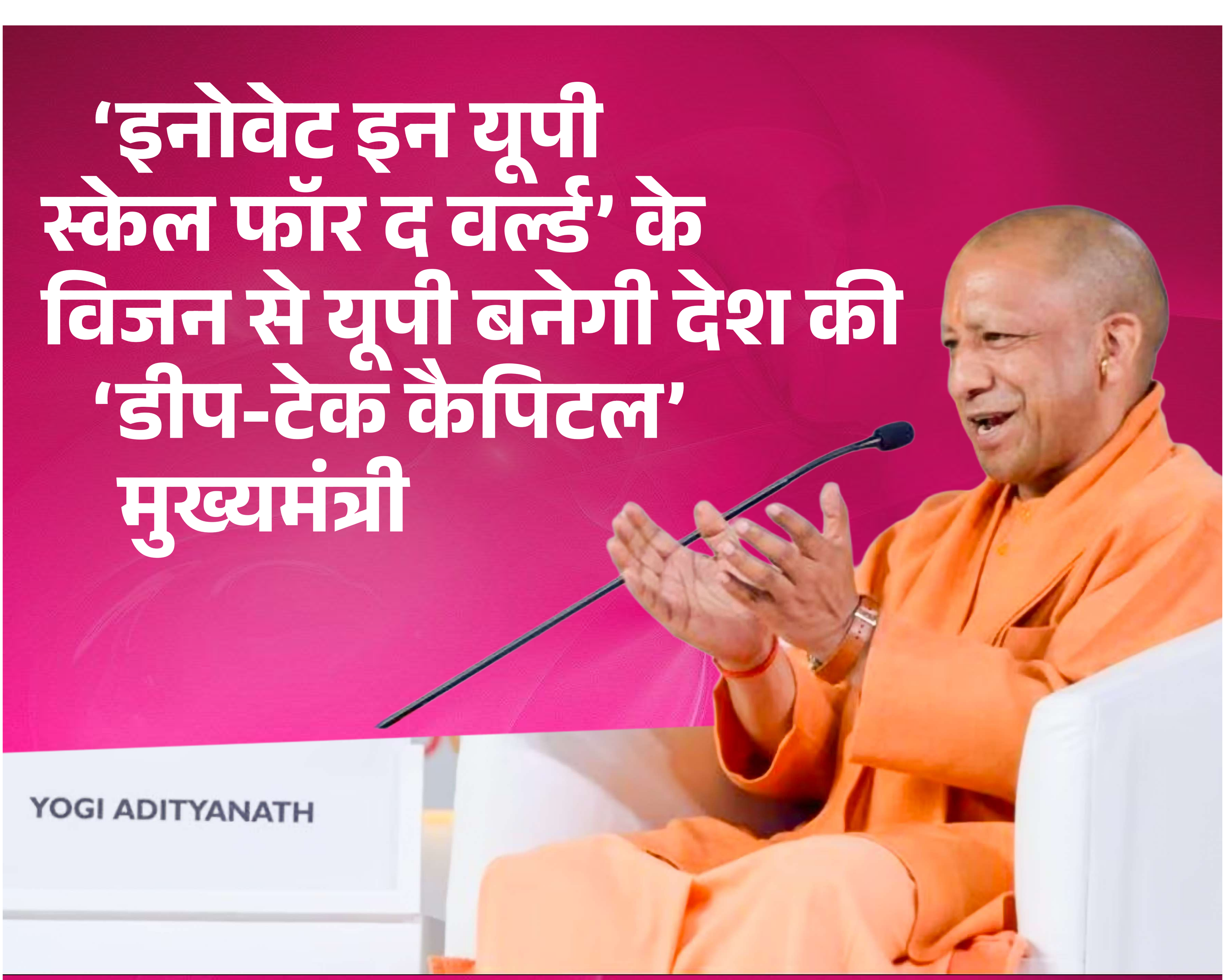

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 अप्रैल 2026 को लखनऊ में आहूत एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि ‘इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड’ के विजन के साथ प्रदेश को देश की ‘डीप-टेक कैपिटल’ बनाने की दिशा में ठोस, परिणामोन्मुखी और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, साइबर सिक्योरिटी और मेड-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने पर बल देते हुए शोध और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि नवाचारों का बड़े स्तर पर व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित हो और रोजगार सृजन को गति मिले।

बैठक में आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। बताया गया कि मेड-टेक के क्षेत्र में गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभिनव तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। यह संस्थान आगामी नवंबर माह में प्रारंभ होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्रदेश के ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसके उत्पादन, भंडारण, परीक्षण, सुरक्षा मानकों एवं औद्योगिक उपयोग के सभी आयामों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुर्वेद के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्लिनिकल वैलिडेशन हेतु देश का पहला संस्थागत केंद्र स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस केंद्र के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, शोध आधार निर्माण, प्रयोगशाला विकास तथा हर्बल संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को विशेष प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्वदेशी ड्रोन निर्माण एवं अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। उन्होंने रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ड्रोन तकनीक में व्यापक स्वदेशीकरण सुनिश्चित करने के प्रयासों को गति देने पर बल दिया। क्वांटम टेक्नोलॉजी को भविष्य की परिवर्तनकारी तकनीक बताते हुए उन्होंने इसके लिए राज्य स्तर पर आवश्यक संसाधन जुटाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि जटिल समस्याओं के समाधान हेतु उन्नत शोध एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सके। स्टार्टअप ईको-सिस्टम पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवाचार की संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाया जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि आईआईटी कानपुर में विकसित स्टार्टअप ईको-सिस्टम के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स इनक्यूबेट किए गए हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही, स्टार्टअप्स को पेटेंट सहायता प्रदान कर नवाचारों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नोएडा में प्रस्तावित ‘यूपी डीप-टेक हब’ को प्रदेश के तकनीकी विकास का केंद्रीय प्लेटफॉर्म बताते हुए निर्देश दिए कि यहां डीप-टेक स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने ‘आईआईटी कानपुर में अनुसंधान, नोएडा से विस्तार और तैनाती’ के मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। बैठक में यह भी बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के माध्यम से प्रदेश में उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान विकसित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की डिजिटल अवसंरचना को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। अंत में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित परियोजनाओं पर विभागीय समन्वय के साथ त्वरित निर्णय लेते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश तकनीकी नवाचार और डीप-टेक विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके।

स्वस्थ नागरिक से ही सशक्त और विकसित भारत का निर्माण संभव, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता जरूरी: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 अप्रैल 2026 को कहा कि स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और यही सशक्त भारत की नींव रखता है। लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित सीएसआई-एनआईसी-2026 (CSI-NIC-2026) के उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित व सशक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में प्रत्येक नागरिक और चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को सम्बद्ध करने वाले इस बेहतरीन विश्वविद्यालय के एक्ट से लेकर निर्माण तक की रुपरेखा उन्होंने स्वयं तैयार की थी, लेकिन पहली बार उन्हें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व के अनुरुप बने इसके भव्य सभागार में भौतिक रूप से उपस्थित होने का अवसर मिला है।

सम्मेलन में गैर-संचारी (नॉन-कम्युनिकेबल) रोगों पर बढ़ती चिंताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती दिनचर्या और स्मार्टफोन पर अत्यधिक समय बिताना कई बीमारियों की जड़ बन रहा है। तेजी से बढ़ता डायबिटीज का दायरा हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की प्राचीन दिनचर्या में समय पर सोना, जगना और पौष्टिक आहार लेना शामिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को वैश्विक मान्यता दिलाई है। बीमारियों से बचाव और उपचार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बचाव पर विशेष ध्यान देते हुए जागरूकता अभियान चलाना वक्त की मांग है। आम लोग डॉक्टरों की बातों को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए चिकित्सकों को समय-समय पर इंटरव्यू और हैंडबिल के माध्यम से लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल के प्रति जागरूक करना चाहिए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक दशक पूर्व किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरे परिवार को आर्थिक रूप से परेशान कर देता था, लेकिन वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' से देश के 55 से 60 करोड़ लोगों को सालाना पांच लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। प्रदेश में जो लोग इस योजना में शामिल नहीं थे, उन्हें 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' से जोड़ा गया है, जिसमें हाल ही में सभी प्रकार के शिक्षकों, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और रसोइयों आदि को भी कवर किया गया है। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंदों के उपचार के लिए लगभग 1,400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी के लिए 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स सफलतापूर्वक संचालित हैं, जबकि एक दशक पूर्व प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज ही थे। प्रत्येक जनपद में आईसीयू स्थापित किए गए हैं और अनेक स्थानों पर कैथ लैब का निर्माण शुरू किया गया है। साथ ही टेलीकंसल्टेशन व वर्चुअल आईसीयू जैसी आधुनिक सुविधाएं एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

सस्ते चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केजीएमयू की ओपीडी में प्रतिदिन 12 से 14 हजार और एसजीपीजीआई की ओपीडी में 10 से 12 हजार मरीज देखे जाते हैं, जबकि एम्स दिल्ली में यह संख्या 16 से 17 हजार है। इतने अधिक मरीजों को क्वालिटी समय देना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती है और अस्त-व्यस्त दिनचर्या के कारण भविष्य में यह दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में व्यापक जन जागरूकता और जीवनशैली में सुधार के बिना इन स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। उन्होंने चिकित्सकों से इस क्षेत्र में निरंतर रिसर्च और इनोवेशन करने का आह्वान किया, जिससे चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा मिल सके और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।

सैनिकों के त्याग से ही सुरक्षित है राष्ट्र, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव: राजनाथ सिंह

मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 अप्रैल 2026 को लखनऊ के सूर्या ऑडिटोरियम में टाइम्स समूह द्वारा आयोजित 'टाइम्स सम्मान समारोह-2026' में सम्मिलित हुए। इस गरिमामय समारोह में शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों एवं उनके परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सैनिकों और उनके परिजनों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं, जिनके त्याग और सर्वोच्च बलिदान के कारण ही पूरा देश आज खुली हवा में सांस ले रहा है। उन्होंने सैनिकों की टीम भावना की सराहना करते हुए कहा कि इसी टीम वर्क और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी (जिम्मेदारी की भावना) के मंत्र से ही भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 1.51 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट भी वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लक्ष्य इसे वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये तक ले जाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैनिकों का ही जिम्मा नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों की एक 'कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी' (सामूहिक जिम्मेदारी) है। देश में कानून का पालन करना, अफवाहों से दूर रहना और देश हित को सर्वोपरि मानना भी राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम योगदान देना है। उन्होंने जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पर भी बल देते हुए कहा कि वर्तमान में 'इन्फॉर्मेशन' (सूचना) भी एक हथियार है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी।

समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीर सैनिकों और उनके परिवारों के अदम्य साहस और त्याग को नमन किया। उन्होंने कहा कि सियाचीन की कंपा देने वाली ठंड हो या रेगिस्तान की तपती रेत, हमारा सैनिक हर परिस्थिति में राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, जिससे 145 करोड़ भारतीय चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सेना कभी भी बहस का विषय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित हैं। सेना व सैनिकों के प्रति हर नागरिक के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश एक महत्वपूर्ण रक्षा हब के रूप में उभर रहा है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जिसने 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपनी मारक क्षमता से दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। इसके साथ ही, चित्रकूट नोड के लिए 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जहां बीईएल कार्य करेगा और झांसी में भारत डायनमिक्स लिमिटेड का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोएडा और कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के कर-कमलों से एक 'स्मृतिका युद्ध स्मारक' का लोकार्पण भी किया गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

समारोह में परमवीर चक्र विजेता श्री योगेन्द्र सिंह यादव के साथ-साथ देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों— श्री करन सिंह (परमवीर चक्र), श्री अब्दुल हमीद (परमवीर चक्र), श्री अरुण खेत्रपाल (परमवीर चक्र), कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय (परमवीर चक्र), कैप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र), मेजर होशियार सिंह (परमवीर चक्र), मो. उस्मान (महावीर चक्र), कोमोडोर अरविन्द सिंह (महावीर चक्र), श्री अनुसूइया प्रसाद (वीर चक्र), नायक राजा सिंह (वीर चक्र), मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह (वीर चक्र), मेजर कमल कालिया (शौर्य चक्र), कर्नल मुनीन्द्र नाथ राय (शौर्य चक्र), लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश चन्द्र शर्मा (शौर्य चक्र), श्री महावीर यादव (शौर्य चक्र), लांसनायक राम बहादुर सिंह (शौर्य चक्र), कैप्टन विष्णु स्वरूप शर्मा (शौर्य चक्र) और श्री हरि सिंह बिष्ट (शौर्य चक्र) के परिजनों को 'टाइम्स सम्मान समारोह-2026' से अलंकृत किया गया।

लखीमपुर खीरी में 817 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 6,706 परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 अप्रैल 2026 को जनपद लखीमपुर खीरी में 817.44 करोड़ रुपये लागत की 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पलिया, श्रीनगर, निघासन और गोला विधानसभा क्षेत्रों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने 'प्रजासुखे सुखं राज्ञः' का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चा शासन वही है जहां जनता सुखी रहे। शासन की खुशी का आधार जनता का कल्याण होना चाहिए, जो संवेदनशीलता से ही संभव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6,706 परिवारों को भौमिक (भूमि) अधिकार पत्र सौंपे, जिनमें 4,356 स्थानीय थारु परिवार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2,350 परिवार शामिल हैं। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, आवास की प्रतीकात्मक चाबी और चेक भी प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिकार पत्र केवल जमीन का कागज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की गारंटी है। अब कोई दबंग इन परिवारों की जमीन पर कब्जा या अवैध वसूली नहीं कर सकेगा। थारु समाज को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए उन्होंने कहा कि वनवासी संस्कृति और शौर्य की इस भूमि के लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके अधिकारों से वंचित रखा। इसी तरह ब्रिटिश काल में यातनाएं सहने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी आजादी के बाद बसाया तो गया, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने दशकों पुराने इस अन्याय को खत्म करते हुए इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि थारु समुदाय के लोगों पर दर्ज किए गए सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

विभिन्न विकास कार्यों का खाका खींचते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गोला-गोकर्णनाथ (छोटी काशी) में श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गोला में देश का पहला पीएलए प्लांट स्थापित हो रहा है और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। पलिया को जल्द ही एयरपोर्ट के माध्यम से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। कृषि और महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 300 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने त्वरित सर्वे कर 24 घंटे के भीतर आपदा राहत कोष और फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के सख्त निर्देश दिए।

लखीमपुर खीरी के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपजाऊ जनपद का वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर था, जो पूर्ववर्ती सरकारों में माफियाओं का अड्डा बन गया था। लेकिन अब यह क्षेत्र दंगा और माफिया मुक्त होकर दुधवा नेशनल पार्क, चन्दन चौकी और अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में जहां भी डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियां हैं, वहां सम्मान स्वरूप बाउंड्रीवॉल और छत्र का निर्माण कराया जाएगा। अंत में उन्होंने 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना के तहत लखीमपुर खीरी के स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने का आह्वान किया।

लखीमपुर खीरी में 331 विस्थापित बंगाली परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक, मियांपुर गांव अब कहलाएगा 'रविन्द्रनगर': सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 अप्रैल 2026 को कहा कि भारतीय परम्परा में धर्म की व्याख्या बहुत सहज और सरल है। विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 'पर हित सरिस धर्म नहिं भाई' के भाव को जीवन में अंगीकार करते हुए कार्य कर रही है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी स्थित मियांपुर में पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र वितरण तथा 417 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 213 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने संविलियन विद्यालय मियांपुर में बच्चों से आत्मीय संवाद भी किया।

विभाजन की त्रासदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बसने वाले बंगाली परिवारों को भौमिक अधिकार देते हुए उन्हें अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। पाकिस्तान के पाप के कारण इन परिवारों पर अत्याचार हुआ और उनकी पैतृक सम्पत्ति पर कुछ दरिन्दों ने कब्जा कर लिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन परिवारों को उनका अधिकार नहीं दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार वर्ष 1947 और 1971 में आए इन विस्थापित परिवारों को उनका हक देने का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों की बस्ती 'मियांपुर' गांव का नाम अब 'रविन्द्रनगर' किया जाएगा। अब इस गांव की पहचान भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर होगी। इस गांव ने पहले ही अपनी सफलता की कहानी लिखी है; यहां के संविलियन विद्यालय की तस्वीर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लगी है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के प्रधान को केंद्र सरकार से पुरस्कार भी मिल चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की भूमि भारत की आध्यात्मिक-विरासत की भूमि है। बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर इन विस्थापित बंगाली परिवारों को उस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है, जिस पर वे वर्षों से बसे थे। यह न्याय, सम्मान और मानवीय पक्ष का प्रतिबिंब है। ये विस्थापित परिवार अपने टूटे हुए सपनों, पीड़ा और अनिश्चित भविष्य के साथ भारत आए थे। हिंदुस्तान ने इन्हें गले लगाया और प्रधानमंत्री के प्रयासों से इन्हें भारत में मालिकाना हक मिल रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री ने इन्हें अधिकार दिया है। 331 विस्थापित परिवारों के सदस्यों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 5,000 से अधिक हो गई है। अब ये अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब कोई इन पर अत्याचार नहीं कर सकता, न ही इन्हें बांग्लादेशी कह सकता है; अब इन्हें पूरे आत्मगौरव और सम्मान के साथ बांग्लाभाषी भारतीय नागरिक कहा जाएगा।

डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और भावी योजनाओं को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं और सिखों की संख्या लगभग 65,000 है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इन सभी हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन परिवारों को मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। भारत के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर भौमिक अधिकार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' नहीं, बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' का विजन साकार हो रहा है। गोला-गोकर्णनाथ शिव मंदिर का भव्य कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और भारत की पहली पीएलए (प्रदूषण मुक्त प्लास्टिक) यूनिट यहां स्थापित हो रही है। मोहम्मदी तहसील के प्रसिद्ध केतकी के फूल को भी वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर जिला प्रशासन को शीघ्र सर्वे कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने और अग्निकांड या तूफान में किसी गरीब का घर नष्ट होने पर उसे तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया आवास उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात,मुख्यमंत्री ने कहा- अब उत्सव है हमारी पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 13 अप्रैल, 2026 को जनपद मुजफ्फरनगर में पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा 951 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 423 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित वृहद रोजगार मेले में उन्होंने 10 चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किये। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की पुस्तक 'कौशल दर्शन' का विमोचन करने के साथ ही देश में विश्वविद्यालयों की रूपरेखा पर आधारित 'एआई सेंटीमेण्ट एण्ड रेडीनेस' रिपोर्ट लॉन्च की। कार्यक्रम में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एनएसडीसी के सीईओ तथा नीति आयोग की डब्लूईपी मिशन डायरेक्टर के मध्य स्टेटमेण्ट ऑफ इण्टेण्ट का आदान-प्रदान भी सम्पन्न हुआ।

महर्षि शुकदेव जी और किसान नेताओं की पावन व कर्मभूमि को नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की गुलामी के कालखण्ड में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने जगन्नाथपुरी से लेकर सोमनाथ और श्री काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम् तक भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया था। काशी विश्वनाथ मन्दिर का पुनर्निर्माण उन्हीं की देन है। उन्होंने जानकारी दी कि लोकमाता की स्मृतियों को जीवन्त बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में 14 श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका योगदान किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए रहा है, इसलिए उन्हें संकीर्ण दायरों में नहीं बांधना चाहिए। सरकार ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के अन्य प्रणेताओं की प्रतिमाओं के सौन्दर्यीकरण और संरक्षण के लिए भी विशेष धनराशि जारी की है।

प्रदेश के विकास और रोजगार परिदृश्य पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुजफ्फरनगर में स्थापित हो रहे सेंटर ऑफ इनोवेशन जैसी सुविधाओं से अब यहां का नौजवान भी एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार ने विगत वर्षों में बिना भेदभाव के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। अन्नदाता किसानों की समृद्धि को देश की खुशहाली का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 122 चीनी मिलें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं और गन्ने से एथेनॉल उत्पादन 200 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। उन्होंने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया कि इस कठिन समय में सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और उन्हें आपदा राहत व फसल बीमा योजना के तहत हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के कल्याण के लिए न्यूनतम मानदेय की गारंटी और 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है।

कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश अब माफिया, दंगा और उपद्रव से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और कांवड़ यात्रा जैसे उत्सव ही उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व जहां पुलिस बल में केवल 10 हजार महिलाएं थीं, वहीं अब 44 हजार बेटियां प्रदेश की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को समय की मांग बताते हुए उन्होंने आधी आबादी के लिए 33 फीसदी आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रैपिड रेल और एक्सप्रेस-वे जैसी उपलब्धियां गिनाईं और मुजफ्फरनगर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए इसे नगर पालिका से नगर निगम में उच्चीकृत कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया।

बाबा साहब की 135वीं जयंती पर 75 जिलों में प्रतिमाओं के संरक्षण का शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। इस गौरवपूर्ण अवसर पर उन्होंने 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्थापित बाबा साहब की 75 प्रतिमाओं के सौंदर्यकरण एवं संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जी ने महासभा परिसर में स्थापित तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डॉ. आंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी को भारतीय संविधान की प्रति तथा स्मृति चिह्न भेंट किया गया। इससे पूर्व उन्होंने हजरतगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का पूरा जीवन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार करने और वंचितों, शोषितों व महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं के चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल और ऊपर छत्र का निर्माण कराया जाएगा, ताकि इन प्रतीकों का सम्मान सुरक्षित रहे और कोई भी अराजक तत्व इन्हें क्षति न पहुँचा सके। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल बाबा साहब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फुले और महाराजा बिजली पासी जैसे सामाजिक न्याय के सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं को इसी प्रकार संरक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए कार्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि प्रदेश में वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवन्तीबाई लोधी और वीरांगना ऊदा देवी पासी के नाम पर पीएसी की तीन महिला बटालियनों का गठन किया गया है। उन्होंने वाराणसी में संत रविदास जी की जन्मभूमि के विकास, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने और लखनऊ में निर्माणाधीन 'डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र' का उल्लेख किया, जिसका द्वितीय चरण जुलाई 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित किए गए 'पंचतीर्थ' और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं—जैसे निःशुल्क राशन, आवास और आयुष्मान कार्ड—बाबा साहब के अंत्योदय के सपने को ही धरातल पर उतार रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने सचेत करते हुए कहा कि जो लोग आज संविधान की प्रति लेकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वे वही स्वार्थी तत्व हैं जिन्होंने हमेशा दलितों और पिछड़ों के उत्थान को बाधित किया। उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा साहब और संत रविदास जी के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों बदले थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब ने स्वयं को अंत तक भारतीय माना था, इसलिए जो लोग तिरंगे, राष्ट्रगान या संविधान का अपमान करते हैं, वे वास्तव में बाबा साहब का अपमान करते हैं। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वे उन ताकतों के वास्तविक चरित्र को पहचानें जो महापुरुषों के नाम पर केवल राजनीति करती आई हैं, जबकि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब और वंचित के मान-सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने टाटा के 10 लाखवें वाहन का किया फ्लैग-ऑफ यूपी बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अप्रैल, 2026 को लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स संयंत्र में निर्मित 10 लाखवें कॉमर्शियल वाहन (इलेक्ट्रिक बस) का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने संयंत्र परिसर और प्रशिक्षण केन्द्र 'गुरुकुल' का अवलोकन किया तथा 'लक्ष्य' प्रोग्राम के तहत चयनित युवाओं को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने 10 लाखवें वाहन की सवारी की और टाटा समूह के अध्यक्ष श्री एन. चन्द्रशेखरन व उनकी टीम को बधाई देते हुए इसे केवल एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक लॉन्च पैड बताया।

प्रदेश की जनसांख्यिकी और विकास की गति को भौतिक विज्ञान के मोमेंटम (द्रव्यमान और गति) से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 56 प्रतिशत युवा वर्कफोर्स है, और डबल इंजन सरकार की गति इस क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने टाटा समूह के प्रति भारतवासियों के अटूट भरोसे की सराहना करते हुए कहा कि घड़ी से लेकर जहाज निर्माण तक हर क्षेत्र में टाटा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की साझेदारी केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समृद्धि और विकास के नए भारत का प्रतीक है।

पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में प्रदेश की खराब कनेक्टिविटी और सुरक्षा के संकट का स्मरण कराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल बन चुका है। उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आगामी गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री जी ने टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट के विजन की सराहना करते हुए कहा कि डीजल और सीएनजी के बाद अब यहाँ बन रहे इलेक्ट्रिक वाहन नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्लांट में अपनाए जा रहे जल संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयासों को प्रगति का वास्तविक आधार बताया।

संयंत्र में कार्यरत 5,600 से अधिक कार्मिकों की लगन की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान टाटा संस के चेयरमैन श्री एन. चन्द्रशेखरन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर को उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप के विश्वास का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 'विकसित उत्तर प्रदेश-2047' के विजन को साकार करने में समूह के पूर्ण सहयोग और मजबूती से अपना योगदान देने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

एआई और आधुनिक तकनीक के दम पर उत्तर प्रदेश भर रहा विकास की नई उड़ान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 15 अप्रैल, 2026 को आयोजित 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश/2047' विजन पर एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (उभरती हुई तकनीक) राज्य के कार्यों और विकास की गति को नई ऊंचाई दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और टाटा संस व टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने विश्वविद्यालय के 'पंचकर्म केन्द्र' का निरीक्षण किया तथा साइबर सिक्योरिटी एवं एआई हैकाथॉन के विजेताओं, 'एआई अवेयरनेस फॉर ऑल' में योगदान देने वाले विद्यार्थियों और 'एआई फॉर फार्मर्स' का प्रशिक्षण लेने वाले किसानों को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी मंच पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जिम्स), ग्रेटर नोएडा के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू का आदान-प्रदान भी संपन्न हुआ।

तकनीक की ताकत का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दशकों से कहर बरपा रही इंसेफेलाइटिस बीमारी पर एआई टूल्स की मदद से प्रभावी अंकुश लगाया गया। वर्ष 2017 से पहले 40 वर्षों में इस बीमारी से 50 हजार से अधिक मौतें हुई थीं। जब राज्य सरकार ने एआई के माध्यम से डेटा एकत्र किया, तो पता चला कि बीमारी का मुख्य कारण अशुद्ध पेयजल और स्वच्छता की कमी थी। इसके बाद प्रभावित बस्तियों में शौचालय और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप विगत 6 वर्षों में मौतों का आंकड़ा शून्य हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई ने बड़ी भूमिका निभाई। डेटा विश्लेषण से यह सामने आया था कि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय का अभाव बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का बड़ा कारण था। सरकार द्वारा इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के बाद बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट 19 प्रतिशत से घटकर मात्र 3 प्रतिशत रह गया।

कृषि और किसानों के विकास में भी तकनीक ने मील का पत्थर साबित होने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रियल टाइम डेटा और एआई के सही उपयोग से उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि विकास दर को 7-8 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। गन्ने की पर्ची की व्यवस्था ऑनलाइन होने से किसानों को दलाली और घटतौली से मुक्ति मिली। वर्ष 2017 से 2025 के बीच गन्ना किसानों को 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये का ऐतिहासिक भुगतान किया गया, जो पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक था। कृषि में ड्रोन के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 'लखपती दीदी' विजन के तहत महिलाएं ड्रोन से मात्र 10 मिनट में एक एकड़ खेत में दवा का समान रूप से छिड़काव कर रही हैं। इसके साथ ही, वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की मदद से तकनीक का प्रयोग कर किसानों ने धान का उत्पादन 40 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचा दिया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल इमरजेंसी के क्षेत्र में भी तकनीक क्रांतिकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में ब्लड या अन्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन बेहद उपयोगी हैं, और इसी को देखते हुए कानपुर व नोएडा में ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा लखनऊ व कानपुर में मेडटेक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने भी एआई को मूलभूत परिवर्तन लाने वाली तकनीक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में यह तकनीक बेहद मददगार होगी। उनके अनुसार, एआई का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव हेल्थकेयर सेक्टर पर पड़ेगा, जिससे न केवल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की पहुंच सुगम होगी, बल्कि कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज और नई दवाओं की खोज में भी अभूतपूर्व सफलता मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में किया टाटा के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे एआई और उन्नत तकनीक के द्वार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अप्रैल 2026 को गोरखपुर स्थित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमपीआईटी) में टाटा समूह के सहयोग से स्थापित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित यह सेंटर युवाओं के भविष्य को संवारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह गोरखपुर ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम-उत्तर बिहार तथा नेपाल की तराई से जुड़े युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए तकनीक का प्रमुख केंद्र बनकर संपूर्ण भारत को नया प्रकाश प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी ने एआई लैब का शुभारंभ किया तथा सेंटर के 'विजन डॉक्यूमेंट' एवं 'इन्क्लूसिव एआई व उत्तर प्रदेश डॉक्यूमेंट' का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप्स पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर एमपीआईटी तथा टीसीएस के संयुक्त प्रयासों से 'एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम' के अंतर्गत एक सप्ताह में सर्वाधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। साथ ही, उनके समक्ष एमपीआईटी और विभिन्न संस्थानों के बीच एमओयू का आदान-प्रदान भी सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन पर टाटा संस के चेयरमैन श्री एन. चंद्रशेखरन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए तैयार किए गए रोडमैप में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक अहम भूमिका निभाएगा। इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कभी राज्य का सबसे पिछड़ा हिस्सा माना जाता था, लेकिन यह सेंटर अब यहां के युवाओं और किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त और समृद्ध बनाएगा।

राज्य में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी जाना जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक्सप्रेस-वे का शानदार नेटवर्क तैयार हुआ है और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित कई अहम परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय आईटीआई को उन्नत बनाया गया है। इसके अलावा, राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फॉरेंसिक लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में टाटा संस के चेयरमैन श्री एन. चंद्रशेखरन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एआई, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकें जीवन में परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। वहीं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सीईओ एवं एमडी श्री के. कृत्तिवासन ने कहा कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दूरगामी प्रभाव होंगे और भारत की तकनीकी प्रगति की यात्रा में टीसीएस, उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करती रहेगी।

उत्तर प्रदेश ई संदेश